भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 629

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

31 आषाढ़, 1948 (शक)

तंजावुर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर

629. श्री मुरसोली एस:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तंजावुर जिले में कार्यरत कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) की संख्या कितनी है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिले में केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की स्थिति क्या है; और
(ग) तंजावुर जिले में साइबर अपराध और/अथवा डेटा धोखाधड़ी संबंधी उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है जो सीईआरटी-इन को रिपोर्ट की गई हैं तथा इन शिकायतों की संख्या, उनकी प्रकृति और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** 31 मई 2026 तक, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कुल 685 सीएससी कार्य कर रहे थे, जिनमें से 486 सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। देश भर में कुल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। तमिलनाडु राज्य में पीएमजीदिशा योजना के तहत, कुल 14.07 लाख+ लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 52,646 लाभार्थियों को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में प्रशिक्षित किया गया। यह योजना 31.03.2024 को समाप्त हो गई है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) अपने 56 स्वयं के केंद्रों और 9000 से अधिक भागीदार संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी), कंप्यूटर अवधारणाओं में जागरूकता (एसीसी), बेसिक कंप्यूटर पाठ्यक्रम (बीसीसी) आदि जैसे पाठ्यक्रमों के द्वारा डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। नाइलिट के डिजिटल साक्षरता (सीसीसी) पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता और डिजिटल वित्तीय सेवाओं पर एक समर्पित घटक शामिल है। मॉड्यूल वित्तीय उपकरणों, सेवाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में बुनियादी जागरूकता प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और डिजिटल वित्तीय प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाया जाता है। नाइलिट का राज्य में कौशल विकास कार्यकलापों के लिए तमिलनाडु में चेन्नई में एक (1) अपना केन्द्र है। इसके अलावा, नाइलिट के राज्य में 35 से अधिक भागीदार

संस्थान हैं, जिनमें तंजावुर जिले के 6 संस्थान शामिल हैं। पिछले 03 वर्षों में, इस नेटवर्क के माध्यम से, नाइलिट ने तमिलनाडु राज्य भर में 37,500+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/कुशल बनाया है।

17 मई, 2020 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में एक व्यापक पहल "पीएम ईविद्या" शुरू की गई थी, जो देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/फीडबैक भी प्रदान करता है।

पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटकों को डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में भी जोड़ा गया है और इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके।

पीएम ई-विद्या 200 डीटीएच टीवी चैनल पहल के तहत, तमिलनाडु राज्य को पांच समर्पित चैनल (टीएन पीएम ईविद्या 158-162) आवंटित किए गए हैं।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने बहुभाषावाद को सक्षम करने वाली स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है।

कुल मिलाकर, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ लर्निंग सेशन पूरे किए जा चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा प्रदान करता है, जिससे शिक्षार्थी इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

हितधारकों के पास दीक्षा पर 836 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में 50-50) तक पहुंच है जो छात्रों को वास्तविक दुनिया के प्रयोगशाला वातावरण के अनुकरण में सहयोग करते हैं।

साइबर अपराध अथवा धोखाधड़ी की शिकायतों की सूचना भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को नहीं दी जाती है। इनकी सूचना साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in/) के माध्यम से गृह मंत्रालय को दी जा रही है।

******